इतवारा बाजार मस्जिद गली का होगा कायाकल्प

महापौर संजय नरवणे ने किया क्षेत्र का अवलोकन : 'प्रतिदिन अखबार' की खबर का असर

प्रतिनिधि, 26 जुलाई

अमरावती- स्थानीय इतवारा बाजार स्थित मस्जिद सड़क के कायाकल्प का मार्ग प्रशस्त हुआ है. बुधवार को महापौर संजय नरवणे ने उक्त सड़क का मुआयना कर बारिश के दिनों में यहां जमा होने वाले पानी की समस्या से अवगत हुए साफ-सफाई की समस्या से लेकर अन्य शिकायतों का निवारण करने का निर्देश मुआयने के दौरान संबंधित

व्यापारियों, ग्राहकों का आना-जाना हुआ दुश्वार

अभियंता को दिया. विदित हो कि प्रतिदिन अखबार के पृष्ठ क्र. 13 पर बुधवार, 23 जुलाई के संस्करण में 'व्यापारियों, ग्राहकों का आना-जाना हुआ दुश्वार' शीर्षक के तहत इतवारा मस्जिद गली की बदहाली की प्रकाशित की गई इस खबर के चलते मनपा प्रशासन में खलबली मच गई. बुधवार को महापौर संजय नरवणे ने स्वयं संबंधित अभियंता व अधिकारियों के साथ इतवारा बाजार व मस्जिद गली का अवलोकन कर मस्जिद गली की सड़क ताबड़तोब निर्माण करने के निर्देश दिए.

शहर का प्रमुख बाजार पेठ इतवारा बाजार इन दिनों अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है. व्यापारियों, ग्राहकों का मुख्य बाजार में आना-जाना दुश्वार सा हो उठा है. इतवारा बाजार की मस्जिद वाली गली इन दिनों जी का जंजाल साबित हो रही है. इस मार्ग से बाजार में प्रवेश करना मानो तार पर कसरत करने जैसा हो. जगह-जगह बने गड्ढे कुछ इस कदर रौद्र रूप लिए हैं कि यहां की सड़क खाई के रूप में तब्दील हो उठी है. जिससे यहां का कारोबार प्रभावित हो रहा है. इस प्रकार की शिकायतें बार-बार बाजार में स्थित व्यवसायियों द्वारा मनपा प्रशासन के समक्ष की गई, लेकिन बीते 3 वर्षों से समस्या जस की तस बरकरार रहने से व्यापारियों में खासा रोष दिखाई दे रहा था. बाजार की समस्याओं को लेकर कुछ व्यापारियों ने प्रतिदिन अखबार से संपर्क किया. प्रतिदिन अखबार ने बाजार की समस्या को प्रमुखता से उजागर करते हुए प्रशासन को अवगत कराया. नतीजतन बुधवार को इतवारा बाजार परिसर का महापौर संजय नरवणे ने मुआयना किया. इस दौरान प्रभारी शहर अभियंता जीवन सदार, सहायक आयुक्त योगेश पीठे, कामेश साहू, राजेश साहू, स्वास्थ्य अधिकारी अजय जाधव, अभियंता जयंत कालमेघ उपस्थित थे.

अमरावती : मस्जिद गली की टूटी-फूटी सड़क को निहारते तथा बाजार व्यापारियों के साथ चर्चा करते महापौर संजय नरवणे व अन्य.

3 वर्षों से समस्या

विगत 3 वर्षों से मस्जिद वाली सड़क की अवस्था खराब है. क्षेत्र के व्यवसायियों ने बार-बार मनपा प्रशासन को इस समस्या से अवगत कराया. लेकिन निराकरण हेतु किसी भी प्रकार का सार्थक कदम प्रशासन की ओर से न उठाए जाने के कारण इस परिसर के व्यापारियों में खासा रोष दिखाई दे रहा था. महापौर के मुआयने के बाद व्यापारियों में आस की ज्योत प्रज्वलित हुई है. महापौर संजय नरवणे के अवलोकन के बाद मस्जिद गली की सड़क कितने दिनों में दुरूस्त की जाएंगी इस ओर इतवारा बाजार के व्यापारियों का ध्यान केंद्रीत हैं.

सफाई का अभाव देख भड़के महापौर

इतवारा बाजार परिसर के मुआयने के दौरान जहां-तहां गंदगी व साफ-सफाई का अभाव महापौर संजय नरवणे को दिखाई दिया. गंदगी को देखकर महापौर खासे नाराज हुए. उन्होंने संबंधित अधिकारी को सख्त लहजे में ताकीद दी कि इस परिसर में नियमित रूप से सफाई होनी चाहिए. कहीं भी पानी जमा नहीं होना चाहिए, ऐसा होने पर प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जाए, ऐसी सिफारिश भी उन्होंने की.

महाराष्ट्र राज्य भारत स्काऊट्स व गाइड्स संस्था के

मुख्य राज्य आयुक्त की अड़चनें दिन-ब-दिन बढ़ रहीं

प्रतिनिधि, 26 जुलाई

अमरावती - महाराष्ट्र राज्य भारत स्काऊट्स व गाइड्स के असंख्य कर्मचारी पिछले 4-5 वर्षों से अपनी भविष्य निर्वाह निधि (ईपीएफ) को लेकर संभ्रम में हैं. वेतन से पीएफ की कटौती की गई, लेकिन उसकी जानकारी नागरिकों को न रहने के कारण संभ्रम निर्माण हुआ है. वेतन से पीएफ की कटौती करने के बाद रकम के विवरण पत्र की जानकारी न मिलने से संभाग के बड़े अधिकारियों की ओर से बड़ा आर्थिक भ्रष्टाचार होने की शंका कर्मचारियों में पनप रही है. इस मामले के संबंध में आवाज उठाने पर अथवा पूछताछ करने पर मुख्य राज्य आयुक्त भा.ई. नगराले अथवा राज्य स्तर पर या जिला स्तर के सहकारी की ओर से कर्मियों को नाहक तकलीफ दी जा रही है. इतना ही नहीं तो कर्मियों को धमकी देने तक का कृत्य करने का आरोप कर्मियों ने लगाया है.

पीएफ का मुद्दा गरमाया

महाराष्ट्र राज्य भारत स्काऊट्स व गाइड्स के राज्यभर में जिला निहाय 90 से अधिक अधिकारी व 300 के करीब विविध गुट के कर्मचारी कार्यरत हैं. राज्य की विविध शालाओं में 15 लाख से अधिक विद्यार्थी स्काउट की शिक्षा ले रहे हैं. पिछले 4-5 वर्षों से विभाग के कर्मियों के वेतन से पीएफ की रकम की कटौती नियमित रूप से की जा रही है लेकिन कटौती की रकम का विवरण कर्मियों को न दिए जाने से रकम कहा जा रही? ऐसा सवाल खड़ा हुआ है. इस संदर्भ में शासन की ओर कर्मियों ने बार-बार लिखित स्वरूप में शिकायत करने पर भी किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई. स्थायी स्वरूप में कर्मियों की ईपीएफ निधि की रकम से सीपीएफ की 12 फीसदी व 2013 के बाद नियुक्त कर्मियों के वेतन से डीसीपीएस के रूप में 10 फीसदी रकम की कटौती की जाती है. 4 वर्षों में यह रकम करोड़ों के आसपास पहुंच गई है. विवरण पत्र में कटौती संबंधित सीपीएफ व डीसीपीएस रकम के लिए राज्य संस्था ने विवरण पत्र कर्मियों को नहीं दिया है. यह सनसनीखेज मामला उजागर हुआ है.

कर्मियों के द्वारा जमा की गई रकम पर इतने फीसदी ब्याज अब तक मिला है, इसका उल्लेख तक नहीं है. कर्मियों को इस संदर्भ में किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं दी जा रही है. शासन इस ओर गंभीरता से ध्यान देकर भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा क्या? इस ओर सभी का ध्यान केंद्रित है.

जनता दल का ठीया आंदोलन कल

अमरावती-जीवनावश्यक वस्तुओं के दाम आसमान छु रहे है. वृद्ध व निराधारों को छोड़कर विधायक-सांसद व नगरसेवकों के वेतन में वृद्धि की जा रही है. वृद्ध व निराधारों की संजय गांधी श्रावण बाल योजना का मानधन बढ़ना आवश्यक है. इनके मानधन में वृद्धि तथा किसानों व खेत मजदूरों को प्रतिमाह 5 हजार रुपए पेंशन दे, इस मांग को लेकर शुक्रवार, 28 जुलाई को जनता दल की ओर से ठिया आंदोलन आयोजित किया है. जिलाधिकारी कार्यालय पर आयोजित आंदोलन में श्रावण बाल योजना व किसान, खेत मजदूर बड़ी संख्या में उपस्थित होकर आंदोलन को सफल बनाने का आह्वान शहराध्यक्ष मोहन खंडारे ने किया है.

विकलांगों का कर्ज माफ करें

राष्ट्रीय अपंग विकास महासंघ की मांग

प्रतिनिधि, 26 जुलाई

अमरावती - राष्ट्रीय अपंग विकास महासंघ की ओर से बुधवार को जिलाधिकारी अभिजीत बांगर को ज्ञापन सौंपकर किसानों की तर्ज पर विकलांगों का कर्ज माफ करने व नए सिरे से कर्ज आवंटित करने की मांग की है.

राष्ट्रीय अपंग विकास महासंघ की ओर से 9 मांगों को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया. केंद्र की तर्ज पर राज्य के मंत्रालय में अपंग विकास विभाग के लिए स्वतंत्र मंत्रालय स्थापित करें, महाराष्ट्र राज्य अपंग वित्त व विकास महामंडल को सामाजिक न्याय विभाग से अलग कर वित्त व नियोजन विभाग में समाविष्ट करें, संजय गांधी निराधार योजना के तहत 2000 रु. पेंशन दें, अपंगों की आय मर्यादा 1 लाख रु. करें, विकलांगों के लिए जिप में 3 फीसदी निधि की व्यवस्था करें, अपंग आयोग की स्थापना करें जैसी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया.

इस दौरान मंगेश धुराटे, प्रा. दीपक गवई, नरेश चंदले, दिलीप बिहाले, नितिन काले, अशोक संखे, सुशील हजारे, सुमित ढोरे, सुभाष माहोरे, पंकज कानपुरे, प्रताप जायसवाल, श्रीराम काले, नीलेश खंडारे, अनिल आठवले, अनिल दुर्योधन आदि उपस्थित थे.

जिले के 82 बांध बारिश में भी प्यासे

17 लघु बांधों ने बढ़ाई चिंता

जिले में 46 लघु बांध हैं. जिसमें से 17 बांधों में अत्यल्प जलसंचय है. अल्प जलसंचय वाले लघु बांधों में पिंपलगांव, सूर्यगंगा, दहीगांव धानोरा, खतिजापुर, गोंडवाघोली, गोंडविहिर, मालखेड़, बासलापुर, टाकली, भिवापुर, जलका, त्रिवेणी, जामगांव, बेलसावंगी, जमालपुर, सावलीखेड़ा, बोबदो व मोगर्दो का समावेश है. इन लघु बांधों में जलसंचय कम होने से चिंता बढ़ी है.

प्रतिनिधि, 26 जुलाई

अमरावती- बारिश का मौसम करीब आधा बीत गया है. 67 फीसद बारिश होने के कारण जिले के 82 बांध प्यासे नजर आ रहे हैं. इन प्रकल्पों में 31.17 फीसद ही जलसंचय है. बांध के क्षेत्र अभी भी मूसलाधार बारिश के इंतजार में हैं. जिले में बारिश के 100 दिन का अनुमान लगाया गया था. जिसके अनुसार वर्तमान में 55 दिन बीत गए हैं. इस कालावधि में 368 मिमी के करीब बारिश होना अपेक्षित था. प्रत्यक्ष में 250.7 मिमी बारिश होने से

मात्र 31 फीसदी ही बचा जलसंचय

यह स्थिति निर्माण हुई है.

गत वर्ष 25 जुलाई तक 528.5 मिमी बारिश हुई थी. विशेष यह है कि बांध क्षेत्र में बारिश नहीं हुई है तथा जिला समेत विदर्भ में एकमेव बड़ा बांध उर्ध्व वर्धा में मध्यप्रदेश से जलसंचय नहीं बढ़ा है. इस बांध का संकल्पित स्तर 564.05 टीएमसी है व जलाशय स्तर 337.32 मीटर है. इसकी तुलना में वर्तमान में 195.80 टीएमसी संचय है. यह 34.71 फीसद है.

बांध में 114.22 टीएमसी जलसंचय रहने से इस बांध का जलसंचय बढ़ा नहीं है. जिले में 4 मध्य बांध हैं. जिसमें शहानूर बांध में 46.4 टीएमसी जलसंचय की तुलना में 18.20 जलसंचय है. पूर्णा बांध में 35.37 में से 3.61 टीएमसी जलसंचय है. बारिश के मौसम में इस प्रकार की स्थिति निर्माण होने से भविष्य में पेयजल का संकट निर्माण हो सकता है, ऐसा जानकारों का कहना है.

मंदिरों में विविध धार्मिक अनुष्ठान : गौंडबाबा व इंद्रशेष बाबा संस्थान में लगेगा मेला

नाग देवता की आराधना में आज शहर होगा मग्न

प्रतिनिधि, 26 जुलाई

अमरावती- समस्त मानव समुदाय और जीव-जंतुओं को विषैले सर्प के दंश से बचाने की कामना व आराधना का पर्व नागपंचमी गुरुवार, 27 जुलाई को बड़े भक्तिभाव के साथ मनाई जाएगी. नागदेवता की आराधना में समूचा शहर मग्न हो उठेगा. नागपंचमी के उपलक्ष्य में एमआईडीसी रोड स्थित गौंडबाबा देवस्थान व वडाली में स्थित इंद्रशेष बाबा संस्थान में मेला लगेगा.

नागपंचमी के पावन पर्व के उपलक्ष्य में शहर के नाग मंदिर में विविध धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है. इस वर्ष नागपंचमी की तिथि को लेकर असमंजस की स्थिति है. पं. करण शर्मा ने बताया कि लोक रीति के अनुसार नागपंचमी पर समस्त नागों के प्रतीकात्मक देवता नागदेव को लाही, गुड़, चना, दूध, जल, काला बुक्का आदि अर्पित कर अर्पण किया जाता है. इस दिन किसी भी वस्तु को धारदार हथियार से नहीं काटते और भूमि नहीं खोदने का विधान है.

अमरावती : गौंडबाबा मंदिर में पूजा का चौरंग सजाते पंडित व इंद्रशेष संस्थान में नागपंचमी के उपलक्ष में भजन प्रस्तुत करती महिलाएं. **फोटो जय स्टूडियो.**

इंद्रशेषबाबा संस्थान में उत्सव शुरू

वडाली परिसर स्थित श्री इंद्रशेष बाबा संस्थान में नागपंचमी उत्सव के उपलक्ष्य में 23 जुलाई से विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है. 24 जुलाई से शिव महापुराण कथा का शुभारंभ किया गया है. हभप कैलाश महाराज भाविकों को शिवपुराण की कथा सुना रहे हैं. प्रतिदिन दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक यह कथा चल रही है. गुरुवार, 27 जुलाई को सुबह 5 बजे श्री की प्रतिमा का अभिषेक करने के बाद पालकी यात्रा व दिंडी नगर परिक्रमा सुबह 10 से दोपहर 1.30 के दौरान निकाली जाएगी. दोप. 2 बजे दर्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया है. 28 जुलाई को सुबह 9 बजे काले का कीर्तन व दोप. 1 बजे विकलांगों में वस्त्र दान व दोपहर 2 बजे महाप्रसाद का वितरण किया जाएगा, ऐसी जानकारी संस्थान के अध्यक्ष राजेश बोके ने दी है.

गौंडबाबा मंदिर में विविध आयोजन

प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी नागपंचमी पर्व पर एमआईडीसी रोड स्थित गौंडबाबा मंदिर में विविध धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए गए हैं. गुरुवार को इस मंदिर में मेले सा वातावरण देखने को मिलेगा.ब्राथी तेली समाज के आराध्य गौंडबाबा के दर्शनार्थ बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर में उपस्थित रहेंगे. नागपंचमी उत्सव के निमित्त महिला मंडल के द्वारा भजन, सुंदरकांड जैसे धार्मिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं.

बस्ते का भारी बोझ ढो रहे छात्र

उपसंचालक को अभी तक नहीं भेजी जांच रिपोर्ट : निर्णय की ओर अनदेखी

प्रतिनिधि, 26 जुलाई

अमरावती- न्यायालय के आदेश के बाद भी छात्रों के बस्ते का बोझ कम नहीं हुआ है. बस्तों के बोझ की जांच के लिए उपसंचालक द्वारा विभाग के सभी जिलों के लिए गटशिक्षाधिकारी, केंद्र प्रमुख और विस्तार अधिकारियों की टीम बनाई गई लेकिन अभी तक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है. जांच रिपोर्ट उपसंचालक के पास प्रस्तुत न किए जाने के चलते बस्ते के बोझ को लेकर विविध प्रकार की चर्चाएं व्याप्त हैं. निर्णय की ओर अनदेखी करने का आरोप भी लगाया जा रहा.

बस्ते का भारी वजन ढ़ो रहे छात्रों को राहत देने के उद्देश्य से न्यायालय ने बोझ कम करने का निर्णय लिया है. न्यायालय के निर्णय के बाद ऐसा प्रतीत हो रहा था कि नन्हे-मुन्नों के कंधों से स्कूली बस्ते का बोझ कम होगा. लेकिन ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है आज भी नर्सरी से लेकर कक्षा 4थीं तक में शिक्षा ग्रहण करने वाले नन्हे-मुन्ने छात्रों की पीठ पर स्कूली बस्ते का बोझ मानो उनके कंधों को झुकाने का कार्य कर रहा है. इस विषय को लेकर कई सामाजिक व शिक्षा संस्थाओं ने आवाज बुलंद की. नन्हीं उम्र में ही क्षमता से अधिक स्कूली बोझ उठाने से विद्यार्थियों का शिक्षा से ध्यान भटक रहा है, ऐसा जानकारों का कहना था. इस मामले की दखल लेते हुए न्यायालय ने बस्ते का भारी बोझ कम करने का निर्णय लिया व इस निर्णय पर शिक्षा विभाग को अमल करने का निर्देश दिए. लेकिन आज भी नन्हे-मुन्नों के कंधों पर बस्ते का बोझ देखने को मिल रहा है.

बदलते समय के साथ शिक्षा प्रणाली में भारी परिवर्तन हो रहा है. परिवर्तन के कारण नये-नये पाठ्यक्रमों को नर्सरी से ही शिक्षा में समाविष्ट किया जा रहा है. जिसके कारण बस्ते का बोझ दिन ब दिन बढ़ने लगा था. न्यायालय ने इस समस्या का निराकरण करते हुए बस्ते का भारी वजन कम करने के लिए फरमान जारी किया. न्यायालय के निर्णय के बाद शिक्षा विभाग ने इस वर्ष बस्ते का बोझ कम करने के लिए पुस्तकों की संख्या में कमी लाई है. इसकी जांच हेतु विभाग ने पड़ताल मुहिम चलाई. 4 दिनों की मुहिम के बाद अधिकारियों ने स्कूलों में जाकर बच्चों व उनके बस्तों की जांच की तो पता चला है कि कई स्कूलों में बस्ते का वजन निर्धारित वजन से अधिक पाया गया.

अमरावती : शाला से भारी भरकम बस्ते को कंधे पर लादे बाहर निकलते छात्र. **फोटो जय स्टूडियो.**

निजी शिक्षा संस्थाओं के कारण स्पर्धा

शिक्षा क्षेत्र में निजी शिक्षा संस्थाओं की भरमार रहने के कारण शिक्षा क्षेत्र में भी भारी स्पर्धा देखने को मिल रही है. शिक्षा संस्थाओं द्वारा विद्यार्थियों को तकनीकी ज्ञान देने के तहत नये-नये पाठ्यक्रमों की शुरूआत की है. नतीजतन इन पाठ्यक्रमों की किताबों से बस्ते का बोझ बढ़ा है. खेलने-कूदने की उम्र में नन्हे-मुन्ने पीठ पर बोरीनुमा बस्ता लादकर जैसे-तैसे स्कूल जाते दिखाई दे रहे थे. न्यायालय ने इस वजन को कम करने के लिए शिक्षा विभाग को ताकिद दी है.

सिंगल हैंड ठेके से शहर की सफाई होगी प्रभावित

पूर्व पार्षद भूषण बनसोड़ की मनपा प्रशासन को राय

प्रतिनिधि, 26 जुलाई

अमरावती- स्थानीय महानगर पालिका प्रशासन की ओर से शहर की सफाई नियमित रूप से शुरू है. सफाई के लिए प्रभाग अथवा वार्ड निहाय ठेकेदार नियुक्त करने की परंपरा है. इस बार 4 सदस्यीय प्रभाग प्रणाली से चुनाव होने के कारण मनपा क्षेत्र में 22 प्रभाग गठित किए गए हैं. इन 22 प्रभागों के सफाई का ठेका 1 मल्टीनेशनल कंपनी को देने की नीति बनाई जा रही है. सफाई के मुद्दे पर सिंगल हैंड ठेका की नीति योग्य नहीं है, इससे शहर की सफाई प्रभावित होगी. कुछ इस प्रकार की राय पूर्व पार्षद भूषण बनसोड़ ने मनपा प्रशासन को देते हुए कहा है कि सिंगल हैंड ठेका प्रणाली छोटे ठेकेदारों पर अन्यायकारक है.

भूषण बनसोड़

कहा-छोटे ठेकेदारों पर होगा अन्याय

निगमायुक्त को सौंपे ज्ञापन के अनुसार सिंगल हैंड ठेके के विषय पर पूर्व पार्षद भूषण बनसोड़ का कहना है कि मनपा क्षेत्र में स्थित प्रभागों की सफाई पर 16 करोड़ का खर्च किया जाता है. शहर की जनसंख्या बहुत अधिक नहीं बढ़ी है और न ही क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है और ऐसे में 10 करोड़ की वृद्धि कर सफाई ठेका सिंगल हैंड में देना न्यायोचित नहीं है. जनता के खून-पसीने की कमाई को इस प्रकार फिजूल खर्च करना अन्यायकारक है. अब तक प्रभागों की सफाई हेतु प्रभाग निहाय ठेकेदार नियुक्त किए जाते थे. महिला बचत गट भी सफाई ठेका का काम देखते थे. एक ही मल्टीनेशनल कंपनी को सफाई का ठेका दिए जाने पर छोटे ठेकेदार क्या करेंगे? इस प्रकार का प्रश्न मनपा प्रशासन से पूछा है. इतने वर्षों तक महानगर पालिका प्रशासन ने इन छोटे ठेकेदार को 10-10 माह के बिल न देते हुए सेवा ली है ऐसे में उक्त निर्णय इन छोटे ठेकेदारों पर अन्याय है.

सफाई की समस्या होगी निर्माण

पूर्व पार्षद भूषण बनसोड़ ने दलील है कि सिंगल हैंड ठेका प्रणाली से सफाई की समस्या निर्माण होगी. जिस कंपनी को ठेका दिया जाएगा, वह कंपनी अगर सब कांट्रेक्टर नियुक्ति करती है तो कंपनी 30 फीसदी व सब कांट्रेक्टर 70 फीसद लेगा. ऐसे में सब कांट्रेक्टर 15 फीसदी कमाएगा व 15 फीसदी सफाई के कार्य पर खर्च करेगा अर्थात सफाई कार्य करने वाले मजदूरों को मात्र 40 फीसद मिलेगा. ऐसे में स्वच्छ भारत अभियान की संकल्पना कैसे साकार होगी? ऐसा सवाल करते हुए बनसोड़ ने सिंगल हैंड ठेके का विरोध किया है.

60 रु. का अतिरिक्त भुर्दंड

भूषण बनसोड़ ने प्रशासन की नीतियों पर सवालिया निशान लगाते हुए ज्ञापन में कहा है कि सफाई के संदर्भ में हर संपत्तिधारक से जो प्रतिमाह 60 रु. लेने की नीति बनाई जा रही है, वह योग्य नहीं है. संपत्ति कर के माध्यम से संपत्ति धारक बड़ा टैक्स अदा कर रहे हैं. इसमें सफाई से संबंधित भी टैक्स हैं. दोहरे टैक्स का बोझ शहर वासियों पर न लादें, ऐसी मांग भी उन्होंने की है.